



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

CH  
27/9/85

सं० 256]  
No. 256]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 25, 1985/आषाढ़ 4, 1907  
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 25, 1985/ASADHA 4, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 25 जून, 1985

अधिसूचना

आय-कर

सा. का. नि. 508 (अ).—भारत सरकार और सीरियाई अरब गणराज्य सरकार के बीच दोहरे कराधान का परिवर्जन और राज्य वित्तीय अपवंचन का निवारण करने के लिए आय पर कर की बाबत उपायद्वय करार दोनों संविदाकारी राज्यों द्वारा अधिसूचित किए जाने पर इस शर्त पर प्रवृत्त हो गया है कि दोनों राज्य उक्त करार के अनुच्छेद 29 द्वारा अपेक्षित के अनुसार अपन-अपन विधियों द्वारा अपेक्षित प्रक्रियाएं पूरा करेंगे।

अतः, केन्द्र सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के धारा 90 और कंपन. (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 (1964 का 7) की धारा 24क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देत है कि उक्त करार के सम. उपबंध भारत संघ में प्रभावी किए जाएंगे।

380 GI/85—1

(1)

भारतीय गणराज्य की सरकार  
और

सीरियाई अरब गणराज्य की सरकार के बीच

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और  
राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए

करार

भारतीय गणराज्य की सरकार और सीरियाई अरब गणराज्य की सरकार, आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए करार सम्पन्न करने के इच्छा से, नीचे लिखे अनुसार सहमत हुई हैं :

अध्याय I

करार का विषय-क्षेत्र

अनुच्छेद 1

वैयक्तिक क्षेत्र

यह करार उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो किस एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों के निवास हैं।

## अनुच्छेद 2

करार के अंतर्गत आने वाले कर

1. यह करार जिन करों पर लागू होगा वे हैं :

(क) भारत के मामले में,

(1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधिन लेगाया गया आयकर जिसमें आय-कर पर कोई अधिभाग भी शामिल है,

(2) कंपनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 (1964 का 7) के अधिन लेगाया गया अतिकर, (जिसे इसके बाद "भारतीय कर" कहा गया है);

(ख) सूरियाई अरब गणराज्य के मामले में : विधायक डिक्री 1949 का संख्या 85 और इसके संशोधनों द्वारा लगाया गया आय-कर (जिसे इसके बाद "सूरियाई कर" कहा गया है)।

2. यह करार किसी भी समरूप अथवा मारतः इस तरह के उन करों पर भी लागू होगा जो वर्तमान करार पर हस्ताक्षर किये जाने की तारीख के पश्चात् इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर दोनों में से किसी भी संविदाकारी राज्य द्वारा लाये जायेंगे। संविदाकारी राज्यों के मक्षम प्राधिकार, उनके अपने अपने करधान कानूनों में जो भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हों उनके संबंध में एक दूसरे को सूचित करेंगे।

## अध्याय II

परिभाषाएं

## अनुच्छेद 3

सामान्य परिभाषाएं

1. इस करार में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो :

(क) "भारत" शब्द से अभिप्रेत है, भारत का राज्यक्षेत्र और उसमें प्रादेशिक समुद्र और उनके ऊपर का आकाश, क्षेत्र तथा राज्य क्षेत्रों, सागर-खंड, महाद्वीपीय मग्न तट भूमि, अन्त्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 (1976 का अधिनियम संख्यांक 80) में उल्लिखित कोई भी अन्य समुद्री क्षेत्र शामिल है, जिसमें भारत के सार्वभौम अधिकार हों और जिस समा तक उनमें इन अधिकारों का उस प्रकार प्रयोग किया जा सकता है, मानों वह समुद्र क्षेत्र भारत के राज्य क्षेत्र का ही एक अंग हो ;

(ख) "सूरिया" शब्द से अभिप्रेत है सूरिया का राज्य क्षेत्र और उसमें इसका निकटवर्ती प्रादेशिक समुद्र तथा उसके ऊपर का आकाश, क्षेत्र शामिल है ;

(ग) "एक संविदाकारी राज्य" और "दूसरे संविदाकारी राज्य" शब्दों से, संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार, भारत अथवा सूरिया अभिप्रेत है ;

(घ) "कर" शब्द से, संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार, भारतीय कर अथवा सूरियाई कर अभिप्रेत है:

परन्तु इसमें ऐसे कोई राशि शामिल नहीं होंगे जो उन करों के संबंध में किस चूक अथवा भूल के संदर्भ में देय हो जिन पर यह करार लागू होता हो अथवा उन करों के संबंध में लगाया गया अर्थदण्ड हो ;

(ङ) "व्यक्ति" शब्द में व्यक्ति, कपता और ऐसे कोई भी अन्य सत्ता शामिल है, जो अलग-अलग संविदाकारी राज्यों में लागू

करधान कानूनों के अंतर्गत कर लगने योग्य इकाई माने जाते हैं ;

(च) "कंपनी" शब्द से कोई ऐसा निगमित निकाय अथवा कोई ऐसा सत्ता अभिप्रेत है, जो अलग-अलग संविदाकारी राज्यों में लागू करधान कानूनों के अंतर्गत एक कंपनी के रूप में मानी जाती है ;

(छ) "एक संविदाकारी राज्य का उद्यम" तथा "दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम" शब्दों से क्रमशः एक संविदाकारी राज्य के किम, निवास द्वारा संचालित उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के निवास द्वारा संचालित उद्यम अभिप्रेत है ;

(ज) भारत के मामले में "मक्षम प्राधिकार" शब्दों से अभिप्रेत है, केन्द्रीय सरकार का वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अथवा उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि; और सूरिया के मामले में वित्त मंत्रालय अथवा उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि ;

(झ) "राष्ट्रिक" शब्द से, किम, संविदाकारी राज्य का, राष्ट्रीयता धारण करने वाला कोई व्यक्ति और कोई भी कानून, व्यक्ति महाभारता अथवा संस्था, जो संविदाकारी राज्य में प्रवृत्त कानून से अपना दैमियत प्राप्त करता हो, अभिप्रेत है।

2. एक संविदाकारी राज्य द्वारा इस करार के उपबन्धों के प्रवर्तन में, किसी शब्द का, जो वहां अन्यथा परिभाषित नहीं हो, संदर्भ की अन्यथा अपेक्षा नहीं होने पर, वही अर्थ होगा जो उस राज्य में लागू उन पर कानूनों के अंतर्गत होता हो जो इस करार के विषय हैं।

## अनुच्छेद 4

आर्थिक अधिवाम

1. इस करार के प्रयोजनों के लिए, "किम, संविदाकारी राज्य का निवास" शब्द से अभिप्रेत है ऐसा कोई व्यक्ति, जिस पर उस राज्य के कानून के अंतर्गत, उसके अधिवाम, निवास, प्रबंध के स्थान अथवा उस प्रकार के किम, अन्य मानदण्ड के कारण वहां पर कर लगने योग्य है।

2. जहां पैराग्राफ 1 के उपबन्धों के कारण, कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवास हो, तो उस स्थिति में इस करार के प्रयोजनों के लिए, उसका निवास, यह दैमियत निम्नलिखित नियमों के अनुसार निश्चित की जाएगी —

(क) वह उस संविदाकारी राज्य का निवास माना जाएगा जिसमें उसे कोई स्थाय निवास-गृह उपलब्ध हो; यदि उसे दोनों संविदाकारी राज्यों में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवास माना जाएगा जिस राज्य के साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध घनिष्ठतर हैं (जिसका उल्लेख इसके बाद उसके "महत्वपूर्ण हितों के केन्द्र" के रूप में किया जाएगा)

(ख) यदि उस संविदाकारी राज्य का निश्चय नहीं किया जा सकता हो, जिसमें उसके महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र है, अथवा यदि उसे किम, संविदाकारी राज्य में कोई निवास गृह उपलब्ध नहीं हो, तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवास माना जाएगा जिसमें वह स्वभावतः रहता हो;

(ग) यदि वह स्वभावतः दोनों ही संविदाकारी राज्यों में रहता है, अथवा उनमें से किम में भी नहीं रहता है तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवास माना जाएगा, जिसका वह राष्ट्रिक है;

(घ) यदि वह दोनों ही संविदाकारी राज्यों का राष्ट्रिक है अथवा उनमें से किम का भी राष्ट्रिक नहीं है, तो संविदाकारी राज्यों के मक्षम प्राधिकार पारस्परिक सहमति द्वारा इस प्रश्न का निर्णय करेंगे।

3. जहां व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति, पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण, दोनों संविदाकारों राज्यो का निवास हो तो वह उस संविदाकार राज्य का निवास माना जाएगा, जिसमें उसका वास्तविक प्रबंध का स्थान स्थित है।

#### अनुच्छेद 5

##### स्थायी संस्थापन

1. इस करार के प्रयोजनों के लिए, “स्थायी संस्थान” शब्दों से कारोबार का वह निश्चित स्थान अभिप्रेत है जहां से उद्यम का कारोबार संपूर्णतः अथवा अंशतः चलाया जाता है।

2. “स्थायी संस्थापन” शब्दों में विशेषतः निम्नलिखित शामिल होंगे :

- (क) प्रबंध का स्थान ;
- (ख) शाखा ;
- (ग) कार्यालय ;
- (घ) कारखाना ;
- (ङ) कर्मशाला ;
- (च) खान, खदान, तेल-क्षेत्र अथवा प्राकृतिक समाधनों के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान ;
- (छ) फार्म, बागान अथवा अन्य स्थान जहां कृषि, बन, बागवान, अथवा तत्संबंधी कार्य किये जाते हैं ;
- (ज) भवन स्थल अथवा निर्माण अथवा संयोजन परियोजना अथवा उनसे संबंधित पर्यवेक्ष, कार्य, जहां इस प्रकार का स्थल, परियोजना अथवा पर्यवेक्ष कार्य बारह महानों से अधिक का अवधि के लिए चालू रहते हों।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, “स्थायी संस्थापन” शब्दों में निम्नलिखित को शामिल नहीं माना जाएगा :

- (क) उद्यम के माल अथवा पण्यों के केवल भण्डारण, प्रदर्शन अथवा सुपुर्दगी के प्रयोजनार्थ सुविधाओं का प्रयोग ;
- (ख) उद्यम के माल अथवा पण्यों का केवल भण्डारण, प्रदर्शन अथवा सुपुर्दगी के प्रयोजनार्थ स्टॉक रखना ;
- (ग) अन्य उद्यम द्वारा केवल संसाधित किये जाने के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अथवा पण्यों का स्टॉक रखना ;
- (घ) उद्यम के लिए माल अथवा पण्यों का केवल क्रय करने अथवा सूचना इकट्ठा करने के प्रयोजनार्थ कारोबार का कोई नियत स्थान रखना ;
- (ङ) उद्यम के व्यापार अथवा कारोबार के संबंध में विज्ञापन के प्रयोजनार्थ, सूचना देने अथवा ऐसे वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यों के लिये जो प्रारम्भिक अथवा सहायक किस्म के हों, कारोबार का नियत स्थान रखना।

4. पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबंधों के होते हुए भी जहां किसी स्वतंत्र हैसियत के अभिकर्ता से भिन्न कोई व्यक्ति जिस पर पैराग्राफ 5 लागू होता हो, किसी उद्यम को और से कार्य कर रहा हो तथा, किसी संविदाकारी राज्य में, उस उद्यम के लिए अथवा उसका और से संविदाएं संपन्न करने के लिए प्राधिकार का प्रायः प्रयोग करता हो, वहां, उन कार्यों के संबंध में जिन्हें वह व्यक्ति उस उद्यम के लिए करता है, उस राज्य में उस उद्यम का स्थायी संस्थापन माना जाएगा यदि ऐसे व्यक्ति को गतिविधियां उद्यम के लिए माल अथवा पण्य खरीदने तक सीमित नहीं हों।

5. किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम का दूसरे संविदाकारी राज्य में माल इस कारण से स्थायी संस्थापन नहीं माना जायेगा कि वह उस दूसरे संविदाकारी राज्य में किसी दलाल, सामान्य कमोशन एजेंट अथवा स्वतंत्र हैसियत वाले किसी अन्य एजेंट के माध्यम से कारोबार करता है, जहां ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार का काम सामान्य रूप से कर रहे हों। लेकिन जब इस प्रकार के एजेंट के क्रियाकलाप उस उद्यम को और से पूर्णरूप से अथवा लगभग पूर्णरूप से किये जाते हैं तो उसे इस पैराग्राफ के अर्थ के अंतर्गत स्वतंत्र हैसियत का एजेंट नहीं माना जायेगा।

6. मात्र इस तथ्य से कि कोई कंपनी, जो किसी एक संविदाकारी राज्य का निवासी हो, किसी ऐसा कंपनी को नियंत्रित करता है अथवा उससे नियंत्रित होता है, जो दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी हो, अथवा जो उस दूसरे संविदाकारी राज्य में (किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा) अपना कारोबार करता हो, इनमें से कोई भी कंपनी खुद किसी दूसरी कंपनी का स्थायी संस्थापन नहीं बन सकती।

7. एक संविदाकारी राज्य के उद्यम का दूसरे संविदाकारी राज्य में उस स्थिति में कोई स्थायी संस्थापन माना जायेगा जब वह कोई ऐसा कारोबार करता हो जिसमें उस दूसरे संविदाकारी राज्य में लोक मनोरंजन-कर्ताओं (जैसे कि थियेटर, चल-चित्र, रेडियो अथवा दूरदर्शन कलाकार और मंगोतकार) अथवा खिलाड़ियों की सेवाओं की व्यवस्था करना शामिल हो, जब तक कि ऐसे उद्यम को प्रत्यक्ष रूप में अथवा अप्रत्यक्ष रूप में, इस प्रकार का सेवाओं की व्यवस्था करने के संबंध में प्रथमोक्त संविदाकारी राज्य को सरकार को लोक-निधियों से पूर्णतः अथवा पर्याप्ततः सहायता प्राप्त नहीं होती हो :

#### अध्याय III

##### आय पर कराधान

#### अनुच्छेद 6

##### अचल संपत्ति से आय

1. अचल संपत्ति से आय पर उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसमें ऐसा संपत्ति स्थित हो।

2. “अचल संपत्ति” शब्दों का परिभाषा उस संविदाकारी राज्य का विधि और व्यवहार के अनुसार की जायेगी जिसमें संबंधित संपत्ति स्थित है। इन शब्दों में किसी भी हालत में यह शामिल होंगे—अचल संपत्ति के अपसाधन के रूप में संपत्ति, कृषि और वानिकी में प्रयुक्त पशुधन तथा उपस्कर, ऐसे अधिकार जिन पर भू-संपत्ति संबंधी सामान्य कानून के उपबंध लागू होते हों, अचल संपत्ति को भोगने के अधिकार, खनिज भण्डार, तेल-क्षेत्र, खदानों, तथा प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण के अन्य स्थानों के संचालन-अधिकार के प्रति फल के रूप में परिवर्तन्य अथवा नियत अदायगियों के अधिकार। पोत तथा विमान अचल संपत्ति नहीं माने जाएंगे।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंध अचल संपत्ति के प्रत्यक्ष प्रयोग से, किराए पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार के प्रयोग से होने वाली आय पर लागू होंगे।

4. पैराग्राफ 1 और 3 के उपबंध किसी उद्यम को अचल संपत्ति से होने वाली आय तथा व्यावसायिक सेवाओं के निष्पादन के लिए इस्तेमाल में आने वाली अचल संपत्ति से होने वाली आय पर भी लागू होंगे।

#### अनुच्छेद 7

##### कारोबार से लाभ

1. एक संविदाकारी राज्य के उद्यम के लाभ केवल उस संविदाकारी राज्य में कराये होंगे। तथापि, यदि उद्यम, दूसरे संविदाकारी राज्य में

स्थित किंसा स्थायी संस्थापन के माध्यम से वहाँ कारोबार कर रहा हो तो उद्यम के लाभों पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा परन्तु कर केवल उतने होंगे लाभों पर लगाया जा सकेगा जो उस स्थायी संस्थापन के कारण हुए माने जा सकते हैं। इससे, प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य द्वारा अपने कर कानूनों के अनुसार ऐसे लाभों पर कर लगाये जाने के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

2. जहाँ एक संविदाकारी राज्य का उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में, वहाँ स्थित किंसा स्थायी संस्थापन के माध्यम से, कारोबार करता है, वहाँ प्रत्येक संविदाकारी राज्य में उस स्थायी संस्थापन के कारण उसको उन लाभों का होना माना जाएगा जिनके प्राप्त होने का तब अपेक्षा रहता है, जब वह, उन्हीं अथवा वैसे ही परिस्थितियों के अधिन, उन्हीं अथवा वैसे ही कार्यों में लगा हुआ स्वतंत्र तथा अलग उद्यम होता, और जिस उद्यम का वह स्थायी संस्थापन है, उसके साथ पूर्णतः स्वतंत्र रूप से व्यवहार करता होता। जहाँ स्थायी संस्थापन के कारण हुए माने जा सकने वाले लाभों की सह-रकम निर्धारित नहीं की जा सकती हो अथवा उसका निर्धारण करना बहुत ही कठिन हो, तो स्थायी संस्थापन के कारण हुए माने जा सकने वाले लाभों का अनुमान उपयुक्त आधार पर लगाया जा सकेगा।

3. किसी स्थायी संस्थापन के लाभों के निर्धारण में उन यथोचित व्ययों की कटौतियों की स्वीकृति दी जायगी, जो स्थायी संस्थापन के कारोबार के प्रयोजनों के लिए किए गए हों, और उनमें इस प्रकार किए गए कार्यकारी तथा सामान्य प्रशासनिक व्यय शामिल रहेंगे, चाहे वे उस राज्य में किए गए हों जहाँ स्थायी संस्थापन स्थित है अथवा अन्यत्र।

4. कोई लाभ केवल इस कारण स्थायी संस्थापन को हुए नहीं माने जायेंगे कि उस स्थायी संस्थापन ने, उद्यम के लिए माल अथवा पण्य वस्तुएं खरीदी हैं।

5. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनों के लिये, स्थायी संस्थापन के कारण हुए माने जाने वाले लाभों को तब तक, उसी पद्धति से वर्षानुवर्ष निर्धारित किया जाएगा जब तक कि उसके विरुद्ध कोई उपयुक्त तथा पर्याप्त कारण नहीं हो।

6. जहाँ आय अथवा लाभों में आय की वे मदें शामिल हों, जिनका इस करार के अन्य अनुच्छेदों में अलग से विवेचन किया गया है, वहाँ उन अनुच्छेदों के उपबंध इस अनुच्छेद के उपबंधों से प्रभावित नहीं होंगे।

#### अनुच्छेद 8

##### विमान परिवहन

1. संविदाकारी राज्य के उद्यम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय यातायात में विमान संचालन से प्राप्त लाभों पर कर केवल उस संविदाकारी राज्य में ही लगाया जायगा, जिसमें उद्यम का प्रभावी प्रबंध का स्थान (अर्थात् प्रधान कार्यालय) स्थित है।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंध, संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा किसी पून, संयुक्त कारोबार अथवा अंतर्राष्ट्रीय संचालन एजेंसी में भाग लेने से अंतर्राष्ट्रीय यातायात में विमान संचालन से होने वाले लाभों के भाग पर भी लागू होंगे।

3. इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिये, अंतर्राष्ट्रीय यातायात में विमान संचालन से संबंध निधियों पर व्याज को, ऐसे विमान के संचालन से होने वाले लाभों के रूप में माना जाएगा और अनुच्छेद 12 के उपबंध इस प्रकार के व्याज के संबंध में लागू नहीं होंगे।

4. "विमान संचालन" शब्दों का अर्थ होगा, विमान के मालिकों अथवा पट्टेदारों अथवा विक्रेताओं (चार्टरर्स) द्वारा वायुयान के जरिये किया जाने वाला व्यक्तियों तथा उनके समान, पशु-धन, माल अथवा डाक

का परिवहन, जिसमें अन्य उद्यमों की ओर से ऐसे परिवहन के लिए टिकटों की विक्री, वायुयान की आकस्मिक पट्टेदारी तथा इस प्रकार के परिवहन से प्रत्यक्षतः सम्बद्ध अन्य कोई भी कार्यकलाप शामिल है।

#### अनुच्छेद 9

##### जहाजरानी

1. एक संविदाकारी राज्य के उद्यम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय यातायात में पोतों के संचालन से प्राप्त लाभों पर कर केवल उस संविदाकारी राज्य में ही लगाया जायगा, जिसमें उद्यम का प्रभावी प्रबंध का स्थान (अर्थात् प्रधान कार्यालय) स्थित है।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंध, संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा किसी पून, संयुक्त कारोबार अथवा अंतर्राष्ट्रीय संचालन एजेंसी में भाग लेने से अंतर्राष्ट्रीय यातायात में पोतों के संचालन से होने वाले लाभों के भाग पर भी लागू होंगे।

3. पैराग्राफ 1, तटवर्ती यातायात के परिणामतः उत्पन्न होने वाले लाभों पर लागू नहीं होगा।

#### अनुच्छेद 10

##### सहयोगी उद्यम

जहाँ:

(क) एक संविदाकारी राज्य का उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के उद्यम के प्रबंध, नियन्त्रण अथवा पूंजी में, प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है, अथवा

(ख) वे ही व्यक्ति, एक संविदाकारी राज्य के उद्यम के और दूसरे संविदाकारी राज्य के उद्यम के प्रबंध नियन्त्रण अथवा पूंजी प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेते हैं,

और दोनों में से किसी भी अवस्था में, दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें रखी अथवा लगाई जाती हैं, जो वैसे शर्तों से भिन्न हैं, जैसी स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाती हैं, तो ऐसे कोई भी लाभ जो, इन शर्तों के नहीं होने की हालत में, उन उद्यमों में से एक को प्राप्त हुए होते, किन्तु इन शर्तों के कारण प्राप्त नहीं हुए तो वे लाभ उस उद्यम के लाभों में सम्मिलित किये जा सकेंगे और उस पर तदनुसार कर लगाया जा सकेगा।

#### अनुच्छेद 11

##### लाभांश

1. एक संविदाकारी राज्य की निवासी किसी कंपनी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किये गये लाभांश, प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में कराधेय नहीं होंगे।

2. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त "लाभांश" पद का अभिप्राय है शेष अथवा अन्य अधिकारों से, जो ऋण-दावे न हों, प्राप्त आय जो लाभ शामिल हों, तथा अन्य निगमित अधिकारों से प्राप्त उस आय से है शेषों अथवा किसी अन्य मद से प्राप्त आय में समाहित हो, जो उस राशि के कराधान कानून द्वारा किसी कंपनी का लाभांश अथवा वितरण माना जाता है, जिसकी वितरण करने वाली कंपनी निवासी है।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि लाभ प्राप्तकर्ता, एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण, ऐसे संविदाकारी राज्य में, जिसकी लाभांश अदा करने वाली कंपनी निवासी हो, उस राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के जरिये कोई कारोबार करता हो अथवा उस अन्य राज्य स्थित किसी निश्चित आधार से उस स्वतंत्र निजी सेवायें करता हो और वह धारणाधिकार, जिसके संबंध लाभांशों की अदायगी की जाती है, ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित

आधार से प्रभावी रूप से संबद्ध हो। इस प्रकार के मामले में, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15 के उपबंध, जैसी भी स्थिति हो, लागू होंगे।

4. जहाँ कोई ऐसी कंपनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी हो, दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, वहाँ वह दूसरा राज्य, कंपनी द्वारा उन व्यक्तियों को दिये गये लाभों पर, जो उस दूसरे राज्य के निवासी नहीं हैं, कोई कर नहीं लगायेगा अथवा कंपनी के अवितरित लाभों पर अवितरित लाभ-कर की किस्म का कोई कर नहीं लागू करेगा, चाहे दिया गया लाभ अथवा अवितरित लाभ, पूर्णतः अथवा अंशतः उस दूसरे राज्य में उत्पन्न होने वाले लाभ अथवा आय के रूप में हो।

#### अनुच्छेद 12

##### व्याज

1. एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को अदा किये जाने वाले व्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जाएगा।

2. तथापि, इस प्रकार के व्याज पर उस संविदाकारी राज्य में भी जिसमें वह अर्जित होता है, और उस राज्य के कानून के अनुसार, कर लगाया जाएगा, किन्तु इस प्रकार लगाये जाने वाले कर की रकम व्याज की सकल रकम के 7.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

3. पैराग्राफ 2 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले तथा दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार को अथवा उसके किसी स्थानीय प्राधिकरण को, उस दूसरे संविदाकारी राज्य के सैन्ट्रल बैंक अथवा उस सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण की, पूर्ण स्वामित्व वाली, किसी एजेंसी को प्रदत्त व्याज पर प्रथमोलिखित संविदाकारी राज्य से कर से छूट दी जायेगी। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारों परस्पर सहमति से किसी भी अन्य सरकारी संस्था को निर्धारित कर सकते हैं, जिस पर यह पैराग्राफ लागू होगा।

4. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त "व्याज" शब्द से सरकारी प्रतिभूतियों बंध-पत्रों अथवा ऋण-पत्रों, चाहे वे बंधक द्वारा प्रतिभूत हों अथवा नहीं और चाहे उनको लाभों में भागीदारी का अधिकार प्राप्त हो, अथवा नहीं, और हर प्रकार के ऋणदावों से प्राप्त आय, और साथ ही अन्य ऐसी सभी आय से अभिप्राय है, जो जिस संविदाकारी राज्य में आय उद्भूत हुई हो, उस राज्य के कराधान कानून के अनुसार उधार दिये गये धन से प्राप्त आय में समाविष्ट की गई हो।

5. पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि व्याज प्राप्तकर्ता, जो कि एक संविदाकारी राज्य का निवासी हो, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में, वहाँ स्थित एक स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारबार चलाता है, अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित किसी निश्चित स्थान से उस में स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएँ करता हो, और जिस ऋणदावे के बारे में व्याज अदा किया गया हो वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा नियत स्थान से प्रभावी रूप में सम्बद्ध हो। इस प्रकार के मामलों में, यथास्थिति, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15 के उपबंध लागू होंगे।

6. किसी संविदाकारी राज्य में व्याज उद्भूत हुआ तब माना जाएगा जब व्याज अदा करने वाला उस संविदाकारी राज्य की सरकार अथवा कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा उस राज्य का निवासी हो। किन्तु, जहाँ व्याज अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, संविदाकारी राज्य में एक स्थायी संस्थापन है, जिसके संबंध में वह ऋण लिया गया था जिस पर व्याज की अदायगी की गई है, और इस प्रकार का व्याज उस स्थायी संस्थापन द्वारा वहन किया जाता है, तब इस प्रकार का व्याज उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ माना जाएगा, जिसमें वह स्थायी संस्थापन स्थित है।

7. जहाँ, व्याज अदा करने वाले तथा प्राप्तकर्ता के बीच, अथवा उन दोनों के और किसी अन्य व्यक्ति के बीच, विशेष प्रकार का संबंध होने के

कारण, व्याज की रकम, उस ऋण-दावे को ध्यान में रखते हुए, जिसके लिए व्याज की रकम अदा की गई है, उस रकम से बढ़ जाती है, जिसके लिए इस प्रकार का संबंध नहीं होने की स्थिति में अदा करने वाले और प्राप्तकर्ता के बीच सहमति हो गई होती, वहाँ इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अन्तिम वर्णित रकम पर ही लागू होंगे। उस मामले में, अदा की गयी रकम के अधिक भाग पर, इस प्रकार के अन्य उपबंधों का अनुपालन करते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जाएगा।

8. इस अनुच्छेद तथा अनुच्छेद 13 के प्रयोजनार्थ, भारत के मामले में "सरकार" पद में कोई भी राज्य सरकार शामिल होगी।

#### अनुच्छेद 13

##### रायल्टियाँ

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली और दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को अदा की गई रायल्टियों पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. तथापि, ऐसी रायल्टियों पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकेगा, जिसमें वे उद्भूत होती हैं, किन्तु इस प्रकार लगाया गया कर ऐसी रायल्टियों की सकल रकम के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त "रायल्टियाँ" शब्द से साहित्यिक, कलात्मक अथवा वैज्ञानिक कृतियों (जिनमें चल-चित्र-फिल्में अथवा रेडियो अथवा दूरदर्शन प्रसारण के लिए फिल्में तथा टेप शामिल हैं), कोई पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन अथवा मॉडल, प्लान, गुप्त फार्मुला अथवा प्रक्रिया के प्रयोग अथवा प्रयोगाधिकार के प्रतिफल के रूप में, अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपस्कर के प्रयोग के लिए प्रयोगाधिकार के लिए अथवा औद्योगिक वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित जानकारी के लिए प्राप्त किसी भी प्रकार की अदायगी अभिप्रेत है।

4. पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि रायल्टियों का प्राप्तकर्ता, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें रायल्टियाँ उद्भूत होती हैं, वहाँ स्थित एक स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारबार चलाता है अथवा उसमें स्थित किसी निश्चित आधार से स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएँ करता है और जिस अधिकार अथवा संपत्ति के संबंध में रायल्टियाँ अदा की गई हों, वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा नियत स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध हो। ऐसे मामले में, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15, जैसा भी माला हो, के उपबंध लागू होंगे।

5. संविदाकारी राज्य में रायल्टियाँ उद्भूत हुई तब मानी जाएंगी, जब रायल्टियाँ अदा करने वाला उस संविदाकारी राज्य की सरकार, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा उस राज्य का कोई निवासी हो। परन्तु जहाँ रायल्टी अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह संविदाकारी राज्य निवासी हो अथवा नहीं, एक संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित आधार है, जिसके संबंध में रायल्टियाँ अदा करने की देनदारी उठायी गई थी, और इस प्रकार की रायल्टियाँ उस स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित आधार द्वारा वहन की जाती हों, तब ऐसी रायल्टियाँ उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुई मानी जायेंगी, जिसमें स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित आधार स्थित है।

6. जहाँ, रायल्टी अदा करने वाले और प्राप्तकर्ता के बीच अथवा उन दोनों के और किसी अन्य व्यक्ति के बीच, विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण, अदा की गयी रायल्टियों की रकम, उसके पैसे इस्तेमाल, अधिकार अथवा सूचना को ध्यान में रखते हुए, जिसके लिये वे रायल्टियाँ अदा की जाती हैं, उस रकम से बढ़ जाती है जिसके लिए इस प्रकार का संबंध नहीं होने की स्थिति में अदा करने वाले और प्राप्तकर्ता के बीच सहमति हो गई होती, वहाँ इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अन्त में उल्लि-

खिला रकम पर लागू होंगे। उस मामले में, अदा की गई रकमों के अधिक भाग पर, इस करार के अन्य उपबंधों का अनुपालन करते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जाएगा।

#### अनुच्छेद 14

##### पूजागत अभिलाष

1. अचल संपत्ति के अंतरण से होने वाले अभिलाष, जैसे कि अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 में परिभाषित हैं, उस संविदाकारी राज्य में कराधेय हों सकेंगे, जिसमें ऐसी संपत्ति स्थित है।

2. ऐसी चल संपत्ति के अंतरण से, जो उस स्थायी संस्थापन की व्यापारिक संपत्ति का एक भाग हो जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित हो, अथवा एक संविदाकारी राज्य के निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य में स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के निष्पादन के प्रयोजनार्थ उपलब्ध किसी निश्चित आधार से संबंधित चल संपत्ति का भाग हो, प्राप्त अभिलाषों पर, जिसमें ऐसे स्थायी संस्थापन (अकेले अथवा संपूर्ण उद्यम के साथ) अथवा ऐसे निर्धारित स्थान के अंतरण से प्राप्त अभिलाष भी शामिल है, उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा।

3. पैराग्राफ 2 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा ऐसे जलपौतों अथवा वायुयानों के अंतरण से, जिन्हें ऐसा उद्यम अंतर्राष्ट्रीय यातायात के अंतर्गत परिचालित करता है तथा इस प्रकार के जलपौतों अथवा वायुयानों के संचालन से संबंधित चल-संपत्ति से प्राप्त लाभ केवल उस राज्य में कराधेय होंगे।

4. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा पैराग्राफ 1, 2 तथा 3 में उल्लिखित संपत्ति से भिन्न किसी भी संपत्ति के अंतरण से प्राप्त लाभ केवल उसी राज्य में कराधेय होंगे।

5. “अंतरण” शब्द का अर्थ संपत्ति का विक्रय, विनिमय, अंतरण अथवा त्याग अथवा उसमें किसी भी अधिकार की समाप्ति अथवा अलग-अलग संविदाकारी राज्यों में प्रवृत्त किसी भी कानून के अंतर्गत उसका अनिवार्य अधिग्रहण है।

#### अनुच्छेद 15

##### स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं

एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा वृत्ति संबंधी सेवाओं अथवा उसी प्रकार के अन्य स्वतंत्र कार्यकलापों के संबंध में प्राप्त आय कर केवल उसी राज्य में लग सकेगा, जब तक कि :—

(क) अपने कार्यकलापों के निष्पादन के प्रयोजनों के निमित्त उसे दूसरे संविदाकारी राज्य में एक निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलब्ध हो ; उस मामले में, उस दूसरे राज्य में उतनी रकम पर कर लगाया जा सकेगा, जो उस निश्चित स्थान के कारण उद्भूत हुई माना जा सकती हो ; अथवा

(ख) वह संगत “पूर्व वर्ष” अथवा “आय वर्ष” में, जैसा भी मामला हो, कुल 183 दिन से अधिक की अवधि-अथवा अवधियों के लिए, अपने कार्यकलापों के प्रयोजनों के निमित्त, दूसरे संविदाकारी राज्य में उपस्थित रहा हो ऐसी स्थिति में उस दूसरे राज्य में केवल उतनी रकम पर कर लगाया जा सकेगा जो उस दूसरे राज्य में किये गये कार्यकलापों के कारण उद्भूत हुई मानी जा सकती हो।

2. “वृत्ति संबंधी सेवाएं” शब्द में स्वतंत्र वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक शैक्षणिक अथवा प्रशिक्षण संबंधी कार्यकलाप तथा चिकित्सकीय अत्यधिकृतिको, दक्रीलो, इंजीनियरों, वास्तुकारों, पत्र-चिकित्सकी तथा लेखाकारों के स्वतंत्र कार्यकलाप भी शामिल हैं।

#### अनुच्छेद 16

##### परिश्रित वैयक्तिक सेवाएं

1. अनुच्छेद 17, 18, 19, 20, 21 तथा 22 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतन, मंजूरी तथा इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर कर केवल उसी राज्य में लग सकेगा, जब तक कि उसका नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में न हो। यदि नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में किया गया हो, तो उससे प्राप्त पारिश्रमिक पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को, दूसरे संविदाकारी राज्य में किये गये नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर कर केवल प्रथमोल्लिखित राज्य में ही लग सकेगा, यदि :—

(क) प्राप्तकर्ता संगत “पूर्व वर्ष” अथवा “आय वर्ष” में, जैसी भी स्थिति हो, कुल 183 दिन से अनधिक की अवधि अथवा अवधियों के लिए दूसरे राज्य में मौजूद रहा है, और

(ख) पारिश्रमिक की अदायगी ऐसे नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से की गई हो, जो दूसरे राज्य का निवासी नहीं है, और

(ग) पारिश्रमिक किसी ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित आधार द्वारा वहन किया गया हो, जो कि उस नियोजक का दूसरे राज्य में है।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय यातायात में जलपौत पर अथवा वायुयान पर किये गये नियोजन के संबंध में पारिश्रमिक पर कर उस संविदाकारी राज्य में लग सकेगा, जिसमें उस उद्यम को प्रभावी प्रबंध व्यवस्था है।

#### अनुच्छेद 17

##### निदेशकों की फीस

एक संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा किसी ऐसी कंपनी के निदेशक-मंडल के एक सदस्य की हैसियत से जो दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है, प्राप्त निदेशक की फीस तथा इसी प्रकार की अदायगियों पर, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा।

#### अनुच्छेद 18

##### कलाकार और खिलाड़ी

1. अनुच्छेद 15 तथा 16 के उपबंधों के होते हुए भी, लोक मनोरंजन कर्ताओं (जैसे थियेटर, चल-चित्र, रेडियो अथवा दूरदर्शन कलाकार तथा संगीतकार) अथवा खिलाड़ियों को अपने व्यक्तिगत कार्यकलापों से प्राप्त आय पर उस संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा, जिसमें ऐसे कार्य किये गये हों :

परन्तु ऐसी आय पर उक्त संविदाकारी राज्य में कर नहीं लग सकेगा, यदि लोक मनोरंजन-कर्ताओं अथवा खिलाड़ियों को उस राज्य की यातायात का व्यय प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार की सार्वजनिक निधियों से पूर्णतः अथवा पर्याप्ततः वहन किया गया हो।

2. इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए “सरकार” शब्द में दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी भी संविदाकारी राज्य का कोई स्थानीय अथवा मासिक प्राधिकरण और भारत के मामले में कोई राज्य सरकार भी सम्मिलित मानी जाएगी।

## अनुच्छेद 19

## सरकारी कार्य

1. एक संविदाकारी राज्य की सरकार द्वारा, किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो उस राज्य का नागरिक है, दूसरे संविदाकारी राज्य में सरकारी कार्य करने के लिए की गई सेवाओं के संबंध में अदा किये गये पारिश्रमिक पर जो पेंशन नहीं है) कर केवल प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में ही लगेगा।

2. किसी भी संविदाकारी राज्य की सरकार द्वारा किसी भी व्यक्ति को, जो दोनों में से किसी भी संविदाकारी राज्य का नागरिक है, अदा की गई किसी भी पेंशन पर कर उम्मी संविदाकारी राज्य में लगाया जा सकेगा, जो पेंशन दे रहा हो।

3. पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबंध किसी भी संविदाकारी राज्य की सरकार द्वारा लाभ के प्रयोजनार्थ चलाये जा रहे व्यापार के संबंध में की गई सेवाओं से संबंधित पारिश्रमिक तथा पेंशन पर लागू नहीं होंगे।

4. इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, "सरकार" शब्द में दोनों संविदाकारी राज्यों का कोई भी स्थानीय अथवा सांविधिक प्राधिकारी और विशेष रूप से, भारतीय रिजर्व बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ सीरिया शामिल होंगे। भारत के मामले में इसमें कोई राज्य सरकार भी शामिल होगी।

## अनुच्छेद 20

## नैर-सरकारी पेंशन एवम् वार्षिकियां

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के स्रोतों से प्राप्त की जा रही किसी भी पेंशन (अनुच्छेद 19 में उल्लिखित पेंशन से भिन्न) अथवा वार्षिकी पर कर केवल प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में लगाया जा सकेगा।

2. "पेंशन" शब्द का अर्थ उस नियतकालिक भुगतान से है जो विगत में की गई सेवाओं के प्रतिफल के रूप में अथवा सेवाओं के निष्पादन के दौरान शारीरिक चाटो की क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त किया जाता हो।

3. "वार्षिकी" शब्द का अर्थ उस उल्लिखित राशि से है जो धन अथवा धन के मूल्य के पर्याप्त अथवा पूरे प्रतिफल के लिए, अदायगियां करने के किसी दायित्व कि अधीन, जीवनपर्यन्त अथवा विनिर्दिष्ट अथवा निश्चय समयावधि के दौरान उल्लिखित समय पर सार्वधिक तौर पर देय होगी।

## अनुच्छेद 21

## विद्यार्थी और प्रशिक्षु

1. विद्यार्थी अथवा व्यवसाय-प्रशिक्षु को, जो एक संविदाकारी राज्य में जाने से तत्काल पूर्व दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था और जो प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में अतन्त्र रूप से अपनी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के उद्देश्य के लिए उपस्थित है, उसे प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में निम्नलिखित के बारे में कर से छूट प्राप्त होगी :—

(क) उस प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य से बाहर रहने वाले व्यक्तियों द्वारा उनके भरण-पोषण, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के उद्देश्यों के लिए, उसको किये गये भुगतान, और

(ख) उस प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में किसी भी "पूर्ववर्ती वर्ष" अथवा "आय वर्ष" के दौरान, जैसी भी स्थिति हो, नियोजन से प्राप्त परिलब्धि जो 15,000 रु. अथवा सीरिया की मुद्रा में उसकी समतुल्य राशि से अधिक न हो, वशत कि ऐसा नियोजन प्रत्यक्षतः उसके अध्ययनों से संबंधित हो, अथवा उसके भरण-पोषण के उद्देश्य से ग्रहण किया गया हो।

2. इस अनुच्छेद के अधीन प्राप्त होने वाले लाभों को केवल ऐसी समयावधि के लिए दिया जाएगा जो सम्बद्ध शिक्षा अथवा प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए यथाचित रूप से अथवा व्यावहारिक रूप से आवश्यक हों, परन्तु इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त लाभ किसी व्यक्ति को थ-मोल्लिखित संविदाकारी राज्य में उसके प्रथम आगमन की तारीख से अगले लगातार पांच वर्षों की अवधि से अधिक समय के लिए प्राप्त नहीं होंगे।

## अनुच्छेद 22

## प्राध्यापक तथा अध्यापक

1. कोई प्राध्यापक अथवा अध्यापक, जो एक संविदाकारी राज्य के किसी विश्व विद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, अथवा किसी अनुमोदित शिक्षण संस्थान में अध्यापन अथवा शोधकार्य करने अथवा दोनों उद्देश्यों के लिए उस संविदाकारी राज्य का दौरा करता है, और जो ऐसे दौरे के तुरन्त पहले दूसरे संविदाकारी राज्य का निवास है अथवा था, उसे ऐसे अध्यापन अथवा शोधकार्य के लिए प्राप्त होने वाली किन्हीं परिलब्धियों पर उस संविदाकारी राज्य में उसके आगमन की तारीख से 12 माह से अधिक की अवधि के लिये कर से छूट प्राप्त होगी।

2. यह अनुच्छेद शोधकार्य से प्राप्त आय पर लागू नहीं होगा यदि ऐसा शोधकार्य मुख्य रूप से किसी विनिष्ट व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निजी लाभों के लिए किया जाता है।

3. इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए और अनुच्छेद 21 के प्रयोजन के लिए भी कोई व्यक्ति किसी संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा यदि वह "पूर्ववर्ती वर्ष" में अथवा "आय के वर्ष" में, जिसमें वह दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करता है अथवा तुरन्त पहले के "पूर्ववर्ती वर्ष" अथवा "आय के वर्ष" में, जैसी भी स्थिति हो, उस संविदाकारी राज्य का निवासी हो।

4. पैराग्राफ 1 के उद्देश्यों के लिए, "अनुमोदित संस्थान का अर्थ उस संस्थान से है, जिसे संबंधित संविदाकारी राज्य के मक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में अनुमोदित किया गया हो।

## अनुच्छेद 23

आय जिसका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है।

एक संविदाकारी राज्य के निवासी की आय की जिन मदों का, जहां कहीं भी उद्भूत होती हो, इस करार के पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में उल्लेख नहीं किया गया है, उन पर केवल उम्मी राज्य में कर लगाया जाएगा।

## अध्याय IV

## दोहरे कराधान के अपाकरण की विधियां

## अनुच्छेद 24

## दोहरे कराधान का अपकरण

1. दोनों संविदाकारी राज्यों में अपने-अपने यहां के प्रचलित कानून, आयकर कराधान पर लागू होते रहेंगे, उन परिस्थितियों को छोड़कर जहां इस करार के अंतर्गत इसके विपरीत प्रावधान किये जायें।

2. जहां भारत के किसी निवासी द्वारा प्राप्त आय पर, इस करार के उपबंधों के अनुसार, सीरिया में कर लगाया जाएगा, भारत में उस निवासी की आय पर लगाये गए कर से उतनी रकम की कटौती दी जाएगी जो कि सीरिया में प्रत्यक्षतः या कटौती द्वारा अदा किये गए आयकर की रकम के बराबर होगी। लेकिन, ऐसी कटौती, भारतीय कर (इस प्रकार की कटौती दिये जाने से पूर्व यथासंगणित) के उस भाग से अधिक नहीं होगी, जो उस आय से प्राप्त हुआ माना जाएगा जिस पर सीरिया में कर लगाया जा सकेगा। इसके अलावा, जहां इस प्रकार की निवासी कोई कंपनी हो, जिसने भारत में अतिकर अदा करना है, वहां उपर्युक्त

कटौती प्रथम बार कंपनी द्वारा भारत में देय आयकर से की जाएगी और शेष रकम की कटौती, यदि कोई हो, तो उसके द्वारा भारत में अदा किये जाने वाले अतिकर से की जाएगी।

3. उपर्युक्त पैरा 2 में उल्लिखित कटौती के प्रयोजन के लिए "सीरिया में अदा किये गये आयकर" में ऐसी कोई भी रकम शामिल समझी जाएगी, जिसे सीरियाई कर के रूप में अदा किया जाता, यदि निम्नलिखित के अन्तर्गत उस वर्ष के लिए कर योग्य आय की संगणना में कटौती या कर से छूट अथवा घटौती स्वीकृत नहीं की जाती:—

- (1) नयी परियोजनाओं को दी जाने वाली छूट के संबंध में 1952 की विधायी डिक्ली 103 अथवा विकास परियोजनाओं में कार्यरत ठेकेदारों को कार्य-निष्पादन की अवधि में राहत देने से संबंधित 1959 की विधि सं. 44 के अनुच्छेद 9, जहां तक उपर्युक्त विधायी डिक्ली तथा अनुच्छेद लागू हैं, तथा जहां इस करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख से अब तक जिनमें संशोधन नहीं किया गया है, अथवा जिनमें केवल बहुत ही मामूली संशोधन किये गए हैं, जिनके फलस्वरूप इनके सामान्य स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो; अथवा
- (2) कोई अन्य उपबन्ध जो कि मार्च, 1982 के पांचवें दिन के पश्चात् अधिनियम किया जाएगा, जिसके अनुसार कर योग्य आय की संगणना में कटौती या कर से छूट अथवा उसमें घटौती की जाएगी, जिसके बारे में संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी सहमत हो कि वह आर्थिक विकास के प्रयोजनों के लिए होगा, यदि बाद में उसमें संशोधन नहीं किया गया हो अथवा उसमें ऐसे मामूली संशोधन किये गए हों, जिनके फलस्वरूप उनके सामान्य स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो।
4. "जहां सीरिया के किसी निवासी की आय, जिस पर इस करार के उपबंधों के अनुसार, भारत में कर लगाया जाएगा, उस निवासी की आय के संबंध में सीरिया कर की उसी कटौती देगा जो कि भारत में प्रत्यक्षतः या कटौती द्वारा अदा किये गए आयकर की रकम के बराबर होगी। लेकिन, इस प्रकार की कटौती, सीरियाई कर (ऐसी कटौती दिये जाने से पूर्व यथा संगणित) के उस भाग से अधिक नहीं होगी, जो उस आय में प्राप्त हुआ माना जाएगा, जिस पर भारत में कर लगाया जाएगा।
5. पैरा 4 में उल्लिखित कटौती के प्रयोजनों के लिए, "भारत में अदा किये गए आयकर" में कोई भी ऐसी रकम शामिल समझी जाएगी, जो भारतीय कर के रूप में देय होती, यदि निम्नलिखित के अन्तर्गत उस वर्ष के लिए कर योग्य आय की संगणना में कटौती अथवा कोई छूट अथवा कटौती स्वीकृत नहीं की गई होती:—

- (1) आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 10(4) 10(4क), 10(6) (VIIक), 10(15) VI, 10(28), 10क, 32क, 33क, 35ख, 54ड, 80जज, 80जज क, 80-अ और 80-उ, जहां तक कि वे इस करार पर हस्ताक्षर किये जाने की तारीख को लागू थी और उक्त तारीख के बाद से उनमें कोई संशोधन नहीं हुआ है, अथवा केवल ऐसे मामूली संशोधन हुए हों, जिनके फलस्वरूप उनके सामान्य स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो; अथवा

- (2) कोई अन्य उपबन्ध, जो कि मार्च, 1982 के पांचवें दिन के पश्चात् अधिनियमित किया जाएगा, जिसके अनुसार कर योग्य आय की संगणना में कटौती या कर से छूट अथवा उसमें घटौती की जाएगी, जिसके बारे में संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी सहमत हो कि वह आर्थिक विकास के प्रयोजनों के लिए होगा, यदि बाद में उसमें संशोधन नहीं किया गया हो

अथवा उसमें ऐसे मामूली संशोधन किये गए हों, जिनके फलस्वरूप उनके सामान्य स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो।

6. जहां इस करार के अन्तर्गत, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य से प्राप्त आय के संबंध में उस संविदाकारी राज्य में कर से छूट प्राप्त हो, तो प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य, उस व्यक्ति की शेष आय पर कर की संगणना करने में कर की वही दर लागू करेगा, जो इस करार के अनुसार कर से छूट दी गई आय को, छूट नहीं दिये जाने की स्थिति में लागू होती।

## अध्याय V

### विशेष उपबंध

#### अनुच्छेद 25

#### सम-व्यवहार

1. एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिकों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसी कोई कराधान व्यवस्था अथवा तत्संबंधी ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी जो उस कराधान से और उन संबंधित अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हो, जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रिकों पर वैसी ही परिस्थितियों में लागू होती हैं अथवा हो सकती हैं।

2. एक संविदाकारी राज्य के उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित स्थायी संस्थापन पर लगाया जाने वाला कर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में उस कर से अपेक्षाकृत कम अनुकूल नहीं होगा जो उस दूसरे राज्य के वैसे ही कार्यों में प्रवृत्त उद्यमों पर उन्हीं परिस्थितियों में लगाया जाता है।

3. इस अनुच्छेद में निहित किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह एक संविदाकारी राज्य को, उस राज्य के निवासी व्यक्तियों को, कराधान के प्रयोजनों के लिये कोई ऐसी वैयक्तिक छूटें गहते, तथा घटौतियां प्रदान करने के लिये बाध्य करता है, जो कानून द्वारा उस राज्य के निवासी व्यक्तियों को ही उपलब्ध हैं।

4. एक संविदाकारी राज्य के उद्यमों पर, जिनकी पूंजी पूर्णतः अथवा अंशतः दूसरे संविदाकारी राज्य के एक अथवा एक से अधिक निवासीयों के, प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः स्वामित्व अथवा नियंत्रण में है, प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में कोई ऐसा कराधान अथवा तत्संबंधी कोई ऐसी अपेक्षा लागू नहीं की जायेगी जो उस कराधान और तत्संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हो जो उस प्रथमोल्लिखित राज्य के अन्य वैसे ही उद्यमों पर उन्हीं परिस्थितियों में लागू होती हैं अथवा हो सकती हैं।

5. इस अनुच्छेद में "कराधान" शब्द-पद का अर्थ वे कर हैं जो इस करार के विषय हैं।

#### अनुच्छेद 26

#### पारस्परिक करार कार्य-विधि

1. जहां किसी संविदाकारी राज्य का कोई निवासी यह समझता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों की कार्यवाहियों के कारण उस पर जो कर लगा है अथवा लगाया जाएगा, वह इस समझने के अन्तर्गत नहीं है, तो वह उन राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों द्वारा उपबंधित उपायों के होते हुए भी अपना समझता उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है, जिसका वह निवासी है। या मामला उस कार्य की सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन वर्षों के अन्दर अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिये, जिसके कारण इस करार के उपबंधों के अन्तर्गत कर नहीं लगाया गया है।

2. यदि मध्यम प्राधिकारी को आपत्ति उचित लगे और यदि वह स्वयं किसी उपयुक्त हल पर पहुँचने में असमर्थ हो तो, वह ऐसे कराधान के परिहार की दृष्टि से जो इस करार के अनुरूप नहीं है, दूसरे संविदाकारी राज्य के मध्यम प्राधिकारी को परस्पर सहमति द्वारा उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा। किये गये किसी भी करार को कार्यान्वित किया जाएगा चाहे संविदाकारी राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों में कोई भी समय-सीमा क्यों न हो।

3. इस करार की व्याख्या करने अथवा इसे लागू करने में यदि कोई कठिनाईयाँ अथवा शंकाएँ उत्पन्न हों, तो संविदाकारी राज्यों के मध्यम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति में हल करने का प्रयास करेंगे। वे उन मामलों में दाहरे कराधान के अपाकरण के लिए परस्पर विचार-विमर्श कर सकते हैं, जिनकी इस करार में व्यवस्था नहीं है।

4. पूर्वोक्त पैराग्राफों के अभिप्राय को लेकर सहमति के प्रयोजनार्थ संविदाकारी राज्यों के मध्यम प्राधिकारी, एक-दूसरे के साथ सीधे पत्र-व्यवहार कर सकते हैं। सहमति होने में जब विचारों का मौखिक आदान-प्रदान उचित प्रतीत होता हो तो ऐसे आदान-प्रदान किसी आयोग के माध्यम से किये जा सकते हैं, जिसमें संविदाकारी राज्यों के मध्यम प्राधिकारियों के प्रतिनिधि हों।

#### अनुच्छेद 27

##### सूचना का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के मध्यम प्राधिकारी ऐसी सूचना अथवा दस्तावेजों का आदान-प्रदान करेंगे जो इस करार के उपबन्धों की कार्यान्वित करने के लिए अथवा उन करों के अपवर्जन को रोकने के लिए आवश्यक है, जो इस करार के विषय हैं। इस प्रकार आदान-प्रदान की गई सूचना अथवा दस्तावेज को गुप्त समझा जाएगा, लेकिन उसे ऐसे व्यक्तियों को (जिनमें न्यायालय अथवा अन्य प्राधिकारी शामिल हैं) प्रकट किया जा सकेगा, जो उन करों के निर्धारण, वसूली, प्रवर्तन, जाँच-पड़ताल अथवा अभियोजन से संबंधित हों, जो इस करार के विषय हैं, अथवा ऐसे व्यक्तियों को प्रकट किया जा सकेगा, जिनसे सूचना अथवा दस्तावेज का संबंध हो।

2. सूचना अथवा दस्तावेजों का आदान-प्रदान या तो तैसी आधार पर होगा अथवा विवेक मामलों के मदर्भ में अनुरोध पर या दोनों ही प्रकार से किया जा सकेगा। तैसी आधार पर दी जाने वाली सूचना अथवा दस्तावेजों की सूची के संबंध में संविदाकारी राज्यों के मध्यम प्राधिकारियों की समग्र-समग्र पर सहमति आवश्यक होगी।

3. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 के उपबन्धों का वह अर्थ नहीं लगाया जाएगा जिसमें कि किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित भार डाला जाए:—

- (क) एक अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य की विधियों अथवा प्रशासनिक प्रथा से हट कर प्रशासनिक उपाय करना;
- (ख) ऐसी सूचना अथवा दस्तावेज देना जो एक अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य की विधियों के अन्तर्गत अथवा प्रणालय के सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है;
- (ग) ऐसी सूचना अथवा दस्तावेज देना, जिसमें व्यापारिक, व्यावसायिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा रोजगार संबंधी ऐसा कोई गुप्त भेद अथवा व्यापारिक-प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होता हो, जिसका प्रकट करना सरकार की नीति के प्रतिकूल हो।

#### अनुच्छेद 28

##### राजनयिक तथा कौसली कार्य

इस करार में विहित किसी व्यवस्था का अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सामान्य नियमों के अन्तर्गत अथवा विशेष करारों के उपबन्धों के अन्तर्गत राजनयिक

अथवा कौसली अधिकारियों के राज्य कर विषयक विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

## अध्याय VI

### अन्तिम उपबंध

#### अनुच्छेद 29

##### प्रवर्तन

प्रत्येक संविदाकारी राज्य, इस करार को लागू करने के लिए उसके कानूनों द्वारा अपेक्षित प्रक्रियाओं के पुरा किये जाने के बारे में दूसरे राज्य को अधिसूचित करेगा। यह करार, इन अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना की तारीख में लागू होगा और उसके बाद—

(क) भारत में—

- (1) वायुयान परिचालन से उत्पन्न आय के मामले में (अनुच्छेद 8 में उल्लिखित) जो कि अप्रैल, 1975 के प्रथम दिन के पश्चात् इस प्रकार के लाभों के संबंध में उत्पन्न हुई हो;
- (2) किसी भी अन्य आय के मामले में, जो कि अप्रैल, 1983 के प्रथम दिन को अथवा के पश्चात् आरम्भ किसी भी कर-निर्धारण वर्ष के लिए कर-निर्धारण योग्य आय के संबंध में हो।

(ख) मौरिया में:—

- (1) वायुयान परिचालन से उत्पन्न आय पर लाभ के मामले में (अनुच्छेद 8 में उल्लिखित), जो कि अप्रैल, 1975 के प्रथम दिन के पश्चात् इस प्रकार के लाभों से प्राप्त हुई हो;
- (2) किसी भी अन्य आय के मामले में, जो कि जनवरी, 1983 के प्रथम दिन को अथवा के पश्चात् आरम्भ किसी कर-निर्धारण वर्ष के लिए कर-निर्धारण योग्य आय के संबंध में हो।

#### अनुच्छेद 30

##### समाप्ति

यह करार अनिश्चित काल तक लागू रहेगा, परन्तु संविदाकारी राज्यों में से कोई भी राज्य, इसके लागू होने की तारीख से पाँच वर्षों की अवधि के समाप्त होने के बाद आरम्भ होने वाले किसी भी कलेण्डर वर्ष में जून के तीसरे दिन को अथवा उससे पहले दूसरे संविदाकारी राज्य को, राजनयिक माध्यमों से समाप्ति का लिखित नोटिस दे सकेगा और वैसी स्थिति में यह करार:—

- (क) भारत में, जिस कलेण्डर वर्ष में समाप्ति का नोटिस दिया गया हो, उसके अगले परवर्ती दूसरे कलेण्डर वर्ष में, और परवर्ती वर्षों में, अप्रैल के प्रथम दिन को शुरू होने वाले किसी कर-निर्धारण वर्ष के लिये कर-निर्धारण योग्य आय के बारे में;
- (ख) मौरिया में, जिस कलेण्डर वर्ष को समाप्ति का नोटिस दिया गया हो, उसके अगले परवर्ती दूसरे कलेण्डर वर्ष में और परवर्ती वर्षों में, पहली जनवरी को आरम्भ होने वाले किसी भी कर-निर्धारण वर्ष के लिये कर-निर्धारण योग्य आय के संबंध में;

निष्प्रभावी हो जाएगा।

जिसके माध्यम से, इसके लिए विधिवत् प्राधिकृत अधीनस्थ अधिकारियों इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

नई दिल्ली में वर्ष एक हजार नौ सौ चौगुनी के फरवरी मास के छठे दिन को अर्थात् हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा में दो मूल प्रतियों में किये गये, सभी पाठ समानतः प्रामाणिक है। दोनों पाठों में समता होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ प्रभावी होगा।

ह/-

(प्रणव मुखर्जी)  
भारत गणराज्य का  
संस्कार की ओर से

ह/-

(डा. हमदी अल-साका)  
सिरिया गणराज्य की  
सरकार की ओर से

[फा. म. 501/1/75-एफ टी. डी.]

एम. एम. नागयणन, अपर सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 25th June, 1985

## NOTIFICATION

## INCOME-TAX

G.S.R. 508(E).—Whereas the annexed Agreement between the Government of India and the Government of the Syrian Arab Republic for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income has entered into force on the notification by both the Contracting States to each other of completion of the procedures required by their respective laws, as required by Article 29 of the said Agreement:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and section 24A of the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Agreement shall be given effect to in the Union of India.

## AGREEMENT

## BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE  
REPUBLIC OF INDIA

## AND

THE GOVERNMENT OF THE SYRIAN ARAB  
REPUBLIC

## FOR

THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION  
AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION  
WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

The Government of the Republic of India and the Government of the Syrian Arab Republic ---

Desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income;

Have agreed as follows:

## CHAPTER I

## SCOPE OF THE AGREEMENT

## Article 1

## PERSONAL SCOPE

This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both the Contracting States.

## Article 2

## TAXES COVERED

1. The taxes to which this Agreement shall apply are:

(a) In the case of India :

- (1) the income-tax including any surcharge thereon imposed under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961);
- (2) the surtax imposed under the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964); (hereinafter referred to as "Indian tax")

(b) In the case of the Syrian Arab Republic: the income tax imposed by the Legislative Decree No. 85 of 1949 and its amendments (hereinafter referred to as "Syrian tax").

2. The Agreement shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed by either Contracting State after the date of signature of the present Agreement in addition to, or in place of, the taxes referred to in paragraph 1 of this Article. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any substantial changes which are made in their respective taxation laws.

## CHAPTER II

## DEFINITIONS

## Article 3

## GENERAL DEFINITIONS

1. In this Agreement, unless the context otherwise requires:

- (a) the term 'India' means the territory of India and includes the territorial sea and airspace above it as well as any other maritime zone referred to in the Territorial Waters Continental Shelf, Exclusive Economic Zone and other Maritime Zones Act 1976 (Act No. 80 of 1975), in which India has sovereign rights and to the extent that these rights can be exercised therein as if such maritime zone is a part of the territory of India;
- (b) the term 'Syria' means the territory of Syria and includes the territorial waters adjacent to and the airspace above it;
- (c) The term "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean India or Syria as the context requires;

- (d) the term "tax" means Indian tax or Syrian tax, as the context requires, but shall not include any amount which is payable in respect of any default or omission in relation to the taxes to which this Agreement applies or which represents a penalty imposed relating to those taxes;
- (e) the term "person" includes an individual, a company and any other entity which is treated as a taxable unit under the taxation laws in force in the respective Contracting States;
- (f) the term "company" means anybody corporate or any entity which is treated as a company under the taxation laws in force in the respective Contracting States;
- (g) the term "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean, respectively, an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
- (h) the term "competent authority" means in the case of India, the Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue) or their authorised representative; and in the case of Syria, the Ministry of Finance or their authorised representative;
- (i) the term "national" means any individual possessing the nationality of a Contracting State and any legal person, partnership or association deriving its status from the laws in force in the Contracting State.

2. In the application of the provisions of this Agreement by a Contracting State, any term not defined herein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws in force in that State relating to the taxes which are the subject of this Agreement.

#### Article 4

##### FISCAL DOMICILE

1. For the purposes of this Agreement, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1, an individual is a resident of both Contracting States, then his residential status for the purposes of this Agreement shall be determined in accordance with the following rules :—

- (a) he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both Contracting States he shall be deemed to be a resident of the Contracting State with which his personal and economic relations are closer (hereinafter referred to as his "centre of vital interests");

- (b) if the Contracting State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he does not have a permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has an habitual abode;
- (c) if he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he shall be deemed to be resident of the Contracting State of which he is a national;
- (d) if he is a national of both Contracting States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1, a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which its place of effective management is situated.

#### Article 5

##### PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Agreement, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" includes especially :—

- (a) a place of management;
- (b) a branch;
- (c) an office;
- (d) a factory;
- (e) a workshop;
- (f) a mine, a quarry, an oilfield or other place of extraction of natural resources;
- (g) a farm, plantation or other place where agricultural, forestry, plantation or related activities are carried on;
- (h) a building site or construction or assembly project or supervisory activities in connection therewith, where such site, project or supervisory activity continues for a period of more than twelve months.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include :—

- (a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;
- (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;
- (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

- (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information for the enterprise.
- (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information or for scientific research, being activities solely of a preparatory or auxiliary character in the trade or business of the enterprise.

4. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person—other than an agent of independent status to whom paragraph 5 applies—is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State, an authority to conclude contracts for or on behalf of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise unless the activities of such person are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise.

5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, where such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise, he will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.

6. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other Contracting State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute for either company a permanent establishment of the other.

7. An enterprise of a Contracting State shall be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State if it carries on a business which consists of providing the services of public entertainers (such as theatre, motion picture, radio or television artistes and musicians) or athletes in that other Contracting State unless the enterprise is directly or indirectly supported wholly or substantially, from the public funds of the Government of the first-mentioned Contracting State in connection with the provision of such services.

### CHAPTER III

### TAXATION OF INCOME

#### Article 6

#### INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income from immovable property may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

2. The term "immovable property" shall be defined in accordance with the law and usage of the Contracting State in which the property is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, oil wells, quarries and other places of extraction of natural resources. Ships and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of professional services.

#### Article 7

#### BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that Contracting State. However, if the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein the profits of the enterprise may be taxed in the other Contracting States but only so much of them as is attributable to that permanent establishment. This is without prejudice to the right of taxation of such profits by the first-mentioned Contracting State according to its tax laws.

2. Where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment. Where the correct amount of profits attributable to a permanent establishment cannot be determined or the determination thereof presents exceptional difficulties, the profits attributable to the permanent establishment may be estimated on a reasonable basis.

3. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions reasonable expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

4. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

5. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method

ar by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

6. Where income or profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

## Article 8

### AIR TRANSPORT

1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of aircraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise (that is, the head office) is situated.

2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to a share of profits from the operation of aircraft in international traffic derived by an enterprise of a Contracting State through participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

3. For the purposes of this Article, interest on loans connected with the operation of aircraft in international traffic shall be regarded as profits derived from the operation of such aircraft, and the provisions of article 12 shall not apply in relation to such interest.

4. The term "operation of aircraft" shall mean the business of transportation by air of persons and their luggage, livestock, goods or mail, carried on by the carriers or lessees or charterers of aircraft, including the sale of tickets for such transportation on behalf of other enterprises, the incidental lease of aircraft and any other activity directly connected with such transportation.

## Article 9

### SHIPPING

1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise (that is, the head office) is situated.

2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to a share of profits from the operation of ships in international traffic derived by an enterprise of a Contracting State through participation in a Pool, a joint business or an international operating agency.

3. Paragraph 1 shall not apply to profits arising as a result of coastal traffic.

## Article 10

### ASSOCIATED ENTERPRISES

Where:

- (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

- (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

## Article 11

### DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall not be taxable in the first-mentioned Contracting State.

2. The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights assimilated to income from shares or any other income which is deemed to be a dividend or distribution of a company by the taxation laws of the Contracting State of which the company making the distribution is a resident.

3. The provisions of paragraph 1 shall not apply if the recipient of the dividends, being a resident of a Contracting State carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case, the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

4. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company to persons who are not residents of that other State, or subject the company's undistributed profits to a tax on undistributed profits even if the dividends paid or the distributed profits consists wholly or partly of profits or income arising in that other State.

## Article 12

### INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the laws of that State, but the tax so charged shall not exceed 7.5 per cent of the gross amount of the interest.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State and paid to the Government of the other Contracting State or a local authority thereof, the Central Bank of that other Contracting State or any agency wholly owned by that Government or local authority shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State. The competent authorities of the Contracting State may determine by mutual agreement any other Government institution to which this paragraph shall apply.

4. The term "interest" as used in this Article means income from Government securities, bonds or debentures, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in profits, and other debt-claims of every kind as well as other income assimilated to income from money lent by the taxation laws of the Contracting State in which the income arises.

5. The provisions of paragraph 1 and 2 shall not apply if the recipient of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is the Government of that Contracting State or a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by that permanent establishment, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

7. Where, owing to special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

8. For the purposes of this Article and Article 13, the term "Government" shall include, in the case of India, any State Government.

#### Article 13

#### ROYALTIES

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the law of that State, but the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties.

3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work (including cinematograph films, or films or tapes used for radio or television broadcasting) any patent, trademark, design or model, plan, secret formula, or process, or for the use of, or the right to use industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the recipient of the royalties, being a resident of a Contracting State carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case, the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is the Government of that Contracting State or a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where, owing to a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of royalties paid, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

#### Article 14

#### CAPITAL GAINS

1. Gains from the alienation of immovable property, as defined in paragraph 2 of Article 6, may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or together with the whole enterprise) or of such a fixed base, may be taxed in that other State.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft which it operates in international traffic and movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in that State.

4. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of any property other than that mentioned in paragraphs 1, 2 and 3 shall be taxable only in that State.

5. The term "alienation" means the sale, exchange, transfer, or relinquishment of the property or the extinguishment of any rights therein or the compulsory acquisition thereof under any law in force in the respective Contracting States.

#### Article 15

##### INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that State unless :

- (a) he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in that case, only so much of the income may be taxed in that other State as is attributable to that fixed base; or
- (b) he is present in the other Contracting State for the purpose of performing his activities for a period or periods exceeding in the aggregate 183 days in the relevant "previous year" or "year of income", as the case may be; in that case, only so much of the income may be taxed in that other State as is attributable to the activities performed in that other State.

2. The term "professional services" includes independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities, as well as the independent activities of physicians, surgeons, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

#### Article 16

##### DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Articles 17, 18, 19, 20, 21 and 22, salaries, wages and other similar

remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other Contracting State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if :

- (a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the relevant "previous year" or "year of income", as the case may be, and
- (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and
- (c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration in respect of an employment exercised abroad a ship or aircraft operated in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

#### Article 17

##### DIRECTORS' FEES

Directors' fees and similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the Board of Directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

#### Article 18

##### ARTISTES AND ATHLETES

1. Notwithstanding the provisions of Articles 15 and 16, income derived by public entertainers (such as theatre, motion picture, radio or television artistes and musicians) or athletes from their personal activities as such may be taxed in the Contracting State in which these activities are exercised :

Provided that such income shall not be taxed in the said Contracting State if the visit of the public entertainers or athletes to that State is directly or indirectly supported, wholly or substantially, from the public funds of the Government of the other Contracting State.

2. For the purpose of this Article, the term "Government" shall include any local or statutory authority of either Contracting State and, in the case of India, any State Government also.

## Article 19

## GOVERNMENT FUNCTIONS

1. Remuneration (not being a pension) paid by the Government of a Contracting State to any individual who is a citizen of that State in respect of services rendered in the discharge of governmental functions in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned Contracting State.

2. Any pension paid by the Government of one of the Contracting States to any individual who is a citizen of either of the two Contracting States shall be taxable only in the Contracting State which is paying the pension.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with any business carried on by the Government of either of the Contracting States for the purposes of profit.

4. For the purposes of this Article, the term "Government" shall include any local or statutory authority of either Contracting State and in particular the Reserve Bank of India and the Central Bank of Syria. In the case of India, it shall also include any State Government.

## Article 20

## NON-GOVERNMENT PENSIONS AND ANNUITIES

1. Any pension (other than a pension referred to in Article 19) or annuity derived by a resident of a Contracting State from sources within the other Contracting State may be taxed only in the first-mentioned Contracting State.

2. The term "pension" means a periodic payment made in consideration of services rendered in the past or by way of compensation for injuries received in the course of performance of services.

3. The term "annuity" means a stated sum payable periodically at stated times, during life or during a specified or ascertainable period of time, under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth.

## Article 21

## STUDENTS AND APPRENTICES

1. A student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned Contracting State solely for the purpose of his education or training, shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State on :

- (a) payments made to him by persons residing outside that first-mentioned Contracting State for the purposes of his maintenance, education or training; and
- (b) remuneration from employment in that first-mentioned Contracting State, in an amount not in excess of Rs. 15,000 or its equivalent

in Syrian currency during any "previous year" or the "year of income", as the case may be, provided that such employment is directly related to his studies or undertaken for the purpose of his maintenance.

2. The benefits of Article shall extend on for such period of time as may be reasonable or customarily required to complete the education or training undertaken, but in no event shall any individual have the benefits of this Article for more than five consecutive years from the date of his first arrival in the first-mentioned Contracting State.

## Article 22

## PROFESSORS AND TEACHERS

1. A professor or teacher who visits a Contracting State for the purpose of teaching or engaging in research, or both, at a university, college, school or other approved institution in that Contracting State and who is, or was immediately before such visit, resident of the other Contracting State, shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State on any remuneration for such teaching or research for a period not exceeding 12 months from the date of his arrival in that Contracting State.

2. This Article shall not apply to income from research if such research is undertaken primarily for the private benefits of a specific person or persons.

3. For the purposes of this Article and Article 21, an individual shall be deemed to be a resident of a Contracting State if he is resident in that Contracting State in the "previous year" or the "year of income", as the case may be, in which he visits the other Contracting State or in the immediately preceding "previous year" or the "year of income".

4. For purpose of paragraph 1, "approved institution" means an institution which has been approved in this regard by the competent authority of the concerned Contracting State.

## Article 23

## INCOME NOT EXPRESSLY MENTIONED

Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Agreement, shall be taxable only in that State.

## CHAPTER IV

## METHODS FOR ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

## Article 24

## ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1. The laws in force in either of the Contracting States shall continue to govern the taxation of income in the respective Contracting State except where provisions to the contrary are made in this Agreement.

2. Where a resident of India derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in Syria, India shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income-tax paid in Syria, whether directly or by deduction. Such deduction shall not, however, exceed that part of the Indian tax (as computed before the deduction is given) which is attributable to the income which may be taxed in Syria. Further, where such resident is a company by which surtax is payable in India, the deduction aforesaid shall be allowed in the first instance from income-tax payable by the company in India and as to the balance, if any, from surtax payable by it in India.

3. For the purposes of the deduction referred to in paragraph 2, "income-tax paid in Syria" shall be deemed to include any amount which would have been payable as Syrian tax but for a deduction allowed in computing the taxable income or an exemption or reduction from tax granted for that year under :—

(i) the Legislative Decree 103 of 1952 regarding exemption of new industrial projects or Article 9 of Law No. 44 of 1959 regarding relief to contractors engaged in development projects during the period of execution, so far as the aforesaid Legislative Decree and Article were in force on, and have not been modified since, the date of the signature of this Agreement, or have been modified only in minor respects so as not to affect their general character ; or

(ii) any other provision which may be enacted after the fifth day of March, 1982 granting a deduction in computing the taxable income or an exemption or reduction from tax which the competent authorities of the Contracting States agree to be for the purposes of economic development, if it has not been modified thereafter or has been modified only in minor respects so as not to affect its general character.

4. Where a resident of Syria derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in India, Syria shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income-tax paid in India, whether directly or by deduction. Such deduction shall not, however, exceed that part of the Syrian tax (as computed before the deduction is given) which is attributable to the income which may be taxed in India.

5. For the purposes of the deduction referred to in paragraph 4, "income-tax paid in India" shall be deemed to include any amount which would have been payable as Indian tax but for a deduction allowed in computing the taxable income or an exemption or reduction from tax granted for that year under :

(i) sections 10(4), 10(4A), 10(6)(viii), 10(15)(iv), 10(28), 10A, 32A, 33A, 35P, 54E, 80HH, 80HHA, 80-I, 80L of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), so far as they were in force on, and have not been

modified since, the date of the signature of this Agreement, or have been modified only in minor respects so as not to affect their general character, or

(ii) any other provision which may be enacted after the fifth day of March, 1982 granting a deduction in computing the taxable income or an exemption or reduction from tax which the competent authorities of the Contracting States agree to be for the purposes of the economic development, if it has not been modified thereafter or has been modified only in minor respects so as not to affect its general character.

6. Where under this Agreement a resident of a Contracting State is exempt from tax in that Contracting State in respect of income derived from the other Contracting State, then the first-mentioned Contracting State may, in calculating tax on the remaining income of that person, apply the rate of tax which would have been applicable if the income exempted from tax in accordance with this Agreement had not been so exempted.

## CHAPTER V

### SPECIAL PROVISIONS

#### Article 25

### NON-DISCRIMINATION

1. The nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities in the same circumstances.

3. Nothing contained in this Article shall be construed as obliging a Contracting State to grant to persons not resident in that State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes which are by law available only to persons who are so resident.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected in the same circumstances.

5. In this Article, the term "taxation" means taxes which are the subject of this Agreement.

## Article 26

## MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with this Agreement, he may, notwithstanding the remedies provided by the national laws of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident. This case must be presented within three years of the date of receipt of notice of the action which gives rise to taxation not in accordance with the Agreement.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at an appropriate solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with this Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the national laws of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Agreement.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

## Article 27

## EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information or document as is necessary for carrying out the provisions of this Agreement or for the prevention of evasion of taxes which are the subject of this Agreement. Any information or document so exchanged shall be treated as secret but may be disclosed to persons (including a court or other authorities) concerned with the assessment, collection, enforcement, investigation or prosecution in respect of the taxes which are the subject of this Agreement, or the persons with respect to whom the information or document relates.

2. The exchange of information or documents shall be either on a routine basis or on request with reference to particular cases or both. The competent authorities of the contracting States shall agree from time to time on the list of the information or documents which shall be furnished on a routine basis.

33. In no case shall be the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation :

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws or administrative practice of that or of the other Contracting State;
- (b) to supply information or documents which are not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State ;
- (c) to supply information or documents which would disclose any trade business, industrial commercial or professional secret or trade process or information the disclosure of which would be contrary to public policy.

## Article 28

## DIPLOMATIC AND CONSULAR ACTIVITIES

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of diplomatic or consular officials under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

## CHAPTER VI

## FINAL PROVISIONS

## Article 29

## ENTRY INTO FORCE

Each of the Contracting States shall notify to the other the completion of the procedures required by its law for the bringing into force of this Agreement. The Agreement shall enter into force on the date of the latter of these notifications and shall thereupon have effect :

(a) In India :

- (i) in the case of profits derived from operation of aircraft (referred to in Article 8), as respects such profits as are derived after the first day of April, 1975 ;
- (ii) in the case of any other income, as respects income assessable for any assessment year commencing on or after the first day of April, 1983.

(b) In Syria :

- (i) in the case of profits derived from operation of aircraft (referred to in Article 8) as respect such profits as are derived after the first day of April, 1975 ;
- (ii) in the case of any other income, as respects income assessable for any assessment year commencing on or after the first day of January, 1983.

## Article 30

## TERMINATION

This Agreement shall continue in effect indefinitely but either of the Contracting States may, on or before the thirtieth day of June in any calendar year beginning after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force, give the other Contracting State through diplomatic channels, written notice of termination and, in such event, this Agreement shall cease to be effective :

- (a) in India, in respect of income assessable for the assessment year commencing on the 1st day of April in the second calendar year next following the calendar year in which the notice is given, and subsequent years ;
- (b) in Syria, in respect of income assessable for any assessment year commencing on the 1st day of January in the second calendar year next following the calendar year in which the notice is given, and subsequent years.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed the present Agreement.

Done on this Sixth day of February one thousand nine hundred and eighty four in New Delhi on two original copies each in the Arabic, Hindi and English languages, all the texts being equally authentic. In case of divergence between the three texts, the English text shall be the operative one.

Sd/-

PRANAB MUKHERJEE

For the Government of India

Sd/-

Dr. HAMDÍ-AL-SAQQA

For the Government of the Republic of Syria.

[F. No. 501/1/75-FTD]

M. S. NARAYANAN, Addl. Secy.

